दृष्टि
The Vision

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

दिसंबर (संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तराखंड **5**

- देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड भंग 5
- एडीबी ने देहरादून और नैनीताल में पेयजल सीवर कार्यों के लिये 938 करोड़ रुपए ऋण को दी मंज़ूरी 5
- रॉकेट इंडिया प्रा. लि. के विस्तार परियोजना का शुभारंभ 6
- सरस मेला 6
- विधिक एवं चिकित्सकीय शिविर 6
- दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा 7
- देहरादून में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 7
- खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन शरदोत्सव मेला 8

नोट :

- दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ 8
- राज्य स्तरीय खेल महाकुम्भ-2021 का उद्घाटन 8
- IISWC और स्पर्श हिमालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 9
- गंगा नौवहन चैनल को स्थिर करने हेतु IIT और IWAI के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 9
- वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश 10
- कॉर्बेट में बनेगा राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव केंद्र 10
- लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 11
- चारधाम परियोजना को मिली सुप्रीम कोर्ट की अनुमति 11
- 'आयुष संवाद" उत्तराखंड आयुष: संसाधन एवं संभावनाएँ 'कार्यक्रम 12
- मुख्यमंत्री ने हवालबाग में दो दिवसीय आजीविका महोत्सव का शुभारंभ किया 12
- 'कोरोना से बचाव: एक सजग पहल' पुस्तक का विमोचन 13
- 'कांडा महोत्सव' 13

नोट :

- सुशासन सूचकांक, 2021 में उत्तराखंड 14
- नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड 15
- वृहद् कौशल एवं सेवायोजन रोज़गार मेले का शुभारंभ 15
- ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल 16
- सुरई इकोटूरिज़्म ज़ोन में जंगल सफारी का शुभारंभ 16
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,547 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया 17

The Vision

नोट :

उत्तराखंड

देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड भंग

चर्चा में क्यों ?

- 30 नवंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम् अधिनियम को निरस्त कर देवस्थानम् बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड को भंग करने का निर्णय इससे संबंधित गठित उच्च स्तरीय समिति व मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा 29 नवंबर, 2021 को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। आगामी विधानसभा सत्र में इस अधिनियम को वापस लिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि 27 नवंबर, 2019 को तत्कालीन सरकार के कैबिनेट ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन विधेयक को मंज़ूरी दी थी और 5 दिसंबर, 2019 को इस विधेयक को विधानसभा में पास किया था तथा 13 जनवरी, 2020 को राज्यपाल द्वारा अनुमति दी गई और 15 जनवरी, 2020 को सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की।
- देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड के अंतर्गत चारधाम- बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री तथा इनसे संबद्ध मंदिरों सहित कुल 51 मंदिर लाए गए। इस बोर्ड का कार्य इन मंदिरों की देख-रेख, आय-व्यय सृजन और विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करने के साथ अन्य सुविधाएँ प्रदान करना था।
- इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष धर्मस्थ व संस्कृति मंत्री बनाए गए थे। वहीं गढ़वाल में मंडलायुक्त रविनाथ रमन को बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था।

एडीबी ने देहरादून और नैनीताल में पेयजल सीवर कार्यों के लिये 938 करोड़ रुपए ऋण को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने उत्तराखंड इंटिग्रेटेड एवं रिसाइलेंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (पेयजल लाइन और सीवर कार्यों) के लिये 938 करोड़ रुपए ऋण की मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड इंटिग्रेटेड एवं रिसाइलेंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत देहरादून के दक्षिण हिस्से में करीब 136 किलोमीटर की पेयजल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे लगभग 40 हज़ार लोगों को पेयजल मिलने की राह आसान हो जाएगी।
- इस प्रोजेक्ट के तहत 5400 घंटों में पानी के मीटर भी लगाए जाएंगे।
- देहरादून में 256 किलोमीटर अंडरग्राउंड सीवर नेटवर्क और 117 किमी. का बरसाती पानी का नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे इस ज़िले के 17 हज़ार 410 घरों के 1 लाख 38 हज़ार लोगों को राहत मिलेगी।
- एडीबी के इस प्रोजेक्ट से देहरादून और नैनीताल में पहली बार कंप्यूटराइज्ड मेंटिनेंस और मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा, जो इन ज़िलों को चार हिस्से में बाँटकर काम करेगा, ताकि तेज़ी से मैनेजमेंट और मेंटिनेंस हो सके।

नोट :

रॉकेट इंडिया प्रा. लि. के विस्तार परियोजना का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 2 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रॉकेट इंडिया प्रा.लि. की नवीनतम विस्तार परियोजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि रॉकेट इंडिया प्रा.लि. कंपनी के विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा।
- इस परियोजना से आने वाले समय में व्यापारियों, कार्मिकों को काफी फायदा होगा।
- इस परियोजना के विस्तार से मक्का इकाई क्षमता भी बढ़कर 1200 टन हो जाएगी, जिससे किसानों को भी लाभ होगा।
- कंपनी को उत्पादों को बनाने के लिये आसानी से मक्का मिलेगा तथा किसानों को उनके मक्का के लिये बाज़ार ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे किसानों और कंपनी दोनों लाभान्वित होंगे।

सरस मेला

चर्चा में क्यों ?

- 2 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के रुद्रपुर स्थित गांधी मैदान में राष्ट्रीय सरस मेला-2021 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन महिलाओं के सशक्तीकरण तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाज़ार देने के उद्देश्य से किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि ग्राम विकास, विभाग द्वारा आयोजित यह मेला 10 दिसंबर तक चलेगा।
- इस मेले में राज्य सरकार द्वारा 119 करोड़ रुपए का पैकेज राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत उन महिला समूहों को दिया गया, जो कोई-न-कोई हुनर रखती हैं।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय सरल मेले में 147 स्वयं सहायता समूहों ने हिस्सा लिया है।
- मुख्यमंत्री ने स्वरोज़गार एवं राज्य के आर्थिकी संसाधनों में वृद्धि हेतु शीघ्रता से ऋण मुहैया कराने के लिये बैंकों को निर्देश दिये हैं।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि रोज़गार एवं स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न रोज़गार योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

विधिक एवं चिकित्सकीय शिविर

चर्चा में क्यों ?

- 5 दिसंबर, 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पिथौरागढ़ में विधिक एवं चिकित्सकीय शिविर का आयोजन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस शिविर का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजीजू, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान ने किया।
- इस शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा चिकित्सा विभाग की ओर से स्टॉल लगाकर मरीजों की जाँच की जा रही है।
- न्याय तक पहुँच के लिये 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक विभिन्न गांव में विधिक शिविर आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया।

नोट :

- केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजीजू ने कहा कि देश की अदालतों का डिजिटलाइजेशन किया जाना है। इसके साथ ही उनमें अन्य जरूरी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्र सरकार ने 9 हज़ार करोड़ रुपए स्वीकृत किये हैं।

दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा

चर्चा में क्यों ?

- 4 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक), चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून का शिलान्यास किया। दून में अत्याधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशाला (सुगंधित पौधों के लिये केंद्र) का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को कुल 18,000 हज़ार करोड़ रुपए की सौगात दी।

प्रमुख बिंदु

- दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 175 किमी. होगी। करीब 8,600 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनाया जाएगा। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये हाईवे बनाया जा रहा है।
- दिल्ली-देहरादून के बीच सड़क से यात्रा का समय आठ घंटे से घटकर करीब ढाई घंटे का सफर हो जाएगा।
- वन्यजीवों के अवरोधरहित आवागमन के लिये यह एशिया का सबसे बड़ा 12 किमी. वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर होगा।
- इस एक्सप्रेस-वे में 500 मीटर के अंतराल पर 750 वे अधिक वर्षा जल संचयन तथा वाटर रिचार्ज प्वाइंट होंगे। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से हरिद्वार की दूरी महज 51 किमी. हो जाएगी, जो करीब 2082 होगी। इस रूट से दिल्ली के लिये हरिद्वार से कनेक्टिविटि आसान हो जाएगी, जिससे सफर का समय घटेगा। इसमें छह इंटरचेंज, चार फ्लाईओवर, छह प्रमुख पुल, 10 माइनर एवं दो आरओरी तथा 10 वीयूपी होंगे।
- आशारोड़ी से गणेशपुर तक तक वन्यजीव बाहुल क्षेत्र है। डाटकाली से गणेशपुर तक एक्सप्रेस-वे एलिवेटड है, इसलिये जंगली जानवरों को क्रॉसिंग में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आशारोड़ी से डाटकाली तक 200 मीटर के दो अंडरपास, 15 से 20 मीटर के छह पुल भी बनेंगी, ताकि जंगली जानवर आसानी से आसानी से आर-पार कर सके।
- गणेशपुर (सहारनपुर) से सवा किमी. एक्सप्रेस-वे पुराने हाईवे के सामांतर बनेगा। इससे आगे डाटकाली तक 14 किमी. का एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे बरसाती नदी के ऊपर बनेगा। डाटकाली में एक और सुरंग बनेगी। छह लेन वाली यह सुरंग 340 मीटर की होगी। यह टनल पहले बनी टनल के सामांतर बनेगी। इस स्थान पर पहले से दो सुरंग बनी हुई है।
- एक्सप्रेस-वे का पहला पार्ट दिल्ली अक्षरधाम से बागपत के पास तक, दूसरा पार्ट बागपत से सहारनपुर बाइपास है। सहारनपुर से गणेशपुर तक पहले ही छह लेन एक्सप्रेस-वे बना है। गणेशपुर से आशारोड़ी तक तीसरा पार्ट है। इसका काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा।

देहरादून में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

- 4-5 दिसंबर, 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में वन अनुसंधान संस्थान (FRI), देहरादून में वर्चुअल मोड में कार्बोहाइड्रेट (कार्बो XXXV) के रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में प्रगति पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के महानिदेशक एएस रावत ने किया।
- इस सम्मेलन में एफआरआई, सीएसआईआर, आईआईटी, आईआईएसईआर प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों सहित भारत, यूएसए, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड तथा पुर्तगाल के शैक्षणिक संस्थानों की 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- इस अवसर पर बोलते हुए एएस रावत ने भोजन और दवा सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनके औद्योगिक महत्व में कार्बोहाइड्रेट की भूमिका पर ज़ोर दिया।

नोट :

- रावत ने खरपतवारों के मूल्य वर्धित उपयोग के लिये नई तकनीकों को विकसित करने पर भी ज़ोर दिया ताकि जंगलों की रक्षा की जा सके और लोगों के लिए आजीविका का स्रोत पैदा किया जा सके।
- क्षेत्र में पहचानी जा रही विभिन्न चुनौतियों के बारे में बोलते हुए, उन्होंने आगे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों से न केवल कार्बोहाइड्रेट की उन्नति के लिये नवीन उपकरण और तकनीक विकसित करने का आह्वान किया, बल्कि पारस्परिक विचारों और लाभ के अनंत अवसरों को बनाने के लिये तथा समाज के कल्याण और राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिये नवाचारों के लिये प्रेरणा हेतु क्रॉस-डिसिप्लिनरी वैज्ञानिक बातचीत और सहयोग को भी बढ़ावा दिया।
- कार्यक्रम के पहले दिन दो तकनीकी सत्र हुए जिसमें भारत, अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड और पुर्तगाल के वक्ताओं द्वारा 10 आमंत्रित व्याख्यान और चार लघु व्याख्यान दिए गए।

खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन शरदोत्सव मेला

चर्चा में क्यों ?

- 7 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली पोखरी में हिमवंत कवि चंद्रकुवर बर्त्वाल खादी ग्रामोद्योग और पर्यटन शरदोत्सव, 2021 मेले का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने मेले का शुभारंभ करते हुए पहाड़ों में उद्योग-धंधों की महत्ता को स्पष्ट करते हुए बताया कि जब पहाड़ों में उद्योग धंधे खुलेंगे तो रोज़गार का सृजन होगा। उन्होंने चमोली पोखरी मेले को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की।
- उल्लेखनीय है कि पोखरी मेले का आयोजन पाँच दिनों के लिये किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने इस मेले के आयोजन के लिये 2 लाख रुपए की राशि देने का भी एलान किया है।

दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 8 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आई.आर.डी.टी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक, देहरादून में दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस दौरान उन्होंने मैदानी क्षेत्रों की दुग्ध समितियों के सचिव हेतु 50 पैसा प्रति लीटर दूध में प्रोत्साहन राशि एवं पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध समितियों के सचिवों हेतु 1 रुपए प्रति लीटर दूध में प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि को 4 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर किये जाने की घोषणा की। साथ ही हल्द्वानी में दुग्ध विकास विभाग के निदेशालय हेतु जल्द-से-जल्द धनराशि जारी करने की घोषणा की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के दूध उत्पादकों की बकाया प्रोत्साहन राशि के लिये 24 करोड़ रुपए प्रदेश भर में स्वीकृत किये गए हैं। ये राशि डेयरी विकास के लिये दी जा रही है। कुल 52 हज़ार मेंबर इस योजना में जुड़ें हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा।
- इस योजना के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादकों को एक करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के ज़रिये दी है।

राज्य स्तरीय खेल महाकुम्भ-2021 का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

- 8 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून ज़िले के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित राज्यस्तरीय खेल महाकुम्भ-2021 का उद्घाटन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राज्यस्तरीय खेल महाकुम्भ-2021 युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित किया गया है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी जवानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार किया है।
- उन्होंने पीआरडी जवानों को वर्षभर में 300 दिन काम देने और ड्यूटी के दौरान किसी जवान की मृत्यु होने पर परिजनों को दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
- इसके अलावा उन्होंने पीआरडी जवानों के मानदेय में 70 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वृद्धि की है तथा साथ ही युवा कल्याण विभाग के ढाँचे का पुनर्गठन की भी घोषणा की।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार राज्य में जल्द ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाएगी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी।

IISWC और स्पर्श हिमालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान (ICAR-IISWC) तथा स्पर्श हिमालय ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, लोगों और संसाधनों को बढ़ावा देने के लिये अंतर-संगठनात्मक सहयोगात्मक कार्यकलापों को निष्पादित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- आईसीएआर-आईआईएसडब्ल्यूसी के निदेशक एम. मधु ने बताया कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सहयोग को प्रोत्साहित करना और सुविधाजनक बनाना तथा पारस्परिक रूप से रुचि रखने वाले सामान्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है, जो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और संबंधित बौद्धिक जीवन एवं सांस्कृतिक विकास के हितों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।
- इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सहयोगात्मक कार्यक्रम और संवर्धित आउटरीच एवं तकनीकी परिणामों और सफलता की कहानियों के बारे में जागरूकता का लक्ष्य रखा जाएगा।
- सहयोग के संभावित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, अनुभव साझा करना और ज्ञान प्रबंधन एवं प्राकृतिक संसाधन आधारित सतत् आजीविका संवर्धन शामिल हैं।
- दोनों संगठन हिमालय के कल्याण पर काम कर रहे अनुसंधान और विकास संगठनों के तकनीकी योगदान एवं सफलता की कहानियों पर जनवरी 2022 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के लिये एक संयुक्त योजना विकसित कर रहे हैं।

गंगा नौवहन चैनल को स्थिर करने हेतु IIT और IWAI के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की ने वाराणसी से साहिबगंज तक गंगा नदी के एक खंड के साथ 17 स्थानों पर नौवहन चैनल के स्थिरीकरण के लिये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रायोजित संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा गंगा के एक पूर्व रूपात्मक अध्ययन का अनुसरण करता है।

प्रमुख बिंदु

- इस परियोजना के तहत आईआईटी रुड़की राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) पर नेविगेशन की क्षमता बढ़ाने के लिये पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों के साथ नेविगेशन चैनल के विकास हेतु गंगा नदी के किनारे 17 स्थानों पर चैनल स्थिरीकरण का (नदी प्रशिक्षण) कार्य करेगा।
- यह कार्य IAWI की चल रही जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP) का एक हिस्सा है, जो विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित है।

नोट :

- जेएमवीपी सड़कों और रेलवे जैसे अन्य सतह परिवहन साधनों के साथ एकीकरण के अवसरों के निर्माण एवं सुधार की परिकल्पना करता है, ताकि विभिन्न अच्छी तरह से सुसज्जित टर्मिनलों और घाटों के माध्यम से जलमार्गों को जोड़कर रसद श्रृंखला की समग्र दक्षता में सुधार किया जा सके।
- इस अवसर पर आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर अजीत के. चतुर्वेदी ने कहा कि यह सहयोग राष्ट्र के जलमार्गों की उन्नति सुनिश्चित करेगा और विशेष रूप से पूरे गंगा बेल्ट में रहने वाले किसानों एवं लोगों को लाभान्वित करेगा।
- यह छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को बढ़ावा देगा, रोज़गार के अवसर पैदा करेगा और कार्गो के परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रकार छोटे जेटीस (Jetties) के माध्यम से रसद में सुधार होगा, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा।

वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश

चर्चा में क्यों ?

- 10 दिसंबर, 2021 को संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने राज्य विधानसभा में चालू वित्त वर्ष के लिये 1,353.7908 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया।

प्रमुख बिंदु

- अनुपूरक बजट में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के लिये 668.36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग की नंदा गौरा योजना के लिये 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- इसी प्रकार राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्यों के लिये लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) हेतु 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पीडब्ल्यूडी के तहत पुलों की मरम्मत और रखरखाव के लिये 50 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।
- गौरतलब है कि मंत्री ने इस वित्तीय वर्ष में सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। इससे पूर्व अगस्त 2021 में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन ने 5,780.80 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया था।
- तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये इस साल 4 मार्च को भारदीसैंण में 57,400.32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।

कॉर्बेट में बनेगा राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव केंद्र

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक राहुल ने बताया कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के ढेला अंचल में 30 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा वन्यजीव बचाव केंद्र राज्य में अपनी तरह का सबसे बड़ा केंद्र होगा।

प्रमुख बिंदु

- इस सेंटर पर वेटनरी सर्जन, फिजीशियन और एनेस्थीसिया एक्सपर्ट समेत 30 लोगों का स्टाफ काम करेगा।
- अब तक तैयार किये गए केंद्र के हिस्से का पहले से ही बाघ, तेंदुए और हाथी के इलाज के लिये उपयोग किया जा रहा है, जबकि पूरा होने के बाद केंद्र भालू, सांप, पक्षियों और अन्य वन्यजीवों का इलाज भी कर सकेगा। वर्तमान में इस केंद्र का उपयोग पाँच तेंदुओं और दो बाघों के उपचार के लिये किया जा रहा है।
- कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद 2019 में इस वन्यजीव बचाव केंद्र की स्थापना की योजना की घोषणा की गई थी।
- परियोजना की कुल लागत लगभग 19 करोड़ रुपए है, जिसमें से अब तक करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं।

नोट :

लिक्विड मिरर टेलीस्कोप

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (AIRES) के वैज्ञानिक दीपांकर बनर्जी ने बताया कि जल्द ही उत्तराखंड में नैनीताल के पास देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जिसे देवस्थली ऑप्टिकल टेलीस्कोप (DOT) के रूप में भी जाना जाता है, स्थापित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- दीपांकर बनर्जी ने बताया कि टेलिस्कोप पहले स्थापित किया जा सकता था, लेकिन राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। उन्होंने कहा कि टेलीस्कोप का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही स्थापित कर उद्घाटन किया जाएगा।
- पारा के साथ लेपित एक तरल दर्पण दूरबीन सामान्य दूरबीन की तुलना में बहुत सस्ती है और यह केवल उन वस्तुओं को अंतरिक्ष में देख सकती है, जो इसके दृश्य में आती हैं, क्योंकि इसे अलग-अलग दिशाओं में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
- इसका उपयोग सितारों, अंतरिक्ष मलबे और उपग्रहों जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिये किया जाएगा, जो इसके फोकस से होकर गुज़रेंगे।
- वर्तमान में, एशिया में इस तरह के सबसे बड़े टेलीस्कोप का व्यास 3.6 मीटर है, जबकि यह टेलीस्कोप चार मीटर व्यास का होगा, जिससे यह स्थापना के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप बन जाएगा।
- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बेल्जियम समकक्ष चार्ल्स मिशेल ने मार्च, 2016 में इस दूरबीन को लॉन्च किया था। इसे कनाडा और बेल्जियम के संयुक्त सहयोग से 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।

चारधाम परियोजना को मिली सुप्रीम कोर्ट की अनुमति

चर्चा में क्यों ?

- 14 दिसंबर, 2021 को केंद्र सरकार की महात्त्वाकांक्षी उत्तराखंड की चारधाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी।

प्रमुख बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतों को देखते हुए उत्तराखंड में चारधाम परियोजना में चीन से लगने वाली सीमा को जोड़ने वाले सामरिक महत्त्व के 3 राष्ट्रीय राजमार्गों, यथा : ऋषिकेश से माना तक, ऋषिकेश से गंगोत्री तक और टनकपुर से पिथौरागढ़ तक, को दो-लेन विन्यास में विकसित करने की सशर्त अनुमति दी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और डबल लेन हाइवे बनाने के लिये केंद्र को अनुमति दी है। यह अनुमति मिलने के बाद चारधाम परियोजना के तहत भारत की चीन तक पहुँच और आसान हो जाएगी तथा किसी भी मौसम में भारतीय सेना चीन से सटी सीमाओं पर पहुँच सकेगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे निर्माण के लिये सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रालय की कोई दुर्भावना नहीं है। अदालत सशस्त्र बलों की ढाँचागत ज़रूरतों का अनुमान नहीं लगा सकती है।
- सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सड़कों को डबल लेन तक चौड़ा करने की अनुमति के साथ ही परियोजना पर सीधे रिपोर्ट करने के लिये पूर्व न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन भी किया है।
- इस समिति के अध्यक्ष को कार्य में तकनीकी सहयोग देने के लिये नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (नीरी) का एक प्रतिनिधि होगा, जिसे निदेशक नामित करेंगे। इस समिति में देहरादून के फारेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट का भी एक प्रतिनिधि होगा, जिसे डायरेक्टर जनरल नामित करेंगे।

नोट :

- कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार व सभी ज़िलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे निगरानी समिति को पूरा सहयोग करेंगे।
- केंद्र सरकार की चारधाम परियोजना का उद्देश्य यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। लगभग 889 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की लागत 12 हज़ार करोड़ रुपए अनुमानित है। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि भारत-चीन वास्तवित नियंत्रण रेखा की ओर से जाने वाली सीमा सड़को के लिये यह फीडर सड़कें हैं।
- केंद्र सरकार परियोजना के तहत सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर तक करना चाहती है। इसके लिये केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके तहत कोर्ट से मांग की गई थी कि वह आठ सितंबर, 2020 को दिये अपने आदेश में संशोधन करे। इस आदेश के तहत सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर तक सीमित करने का आदेश दिया गया था।

'आयुष संवाद" उत्तराखंड आयुष: संसाधन एवं संभावनाएँ'कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

- 16 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय पोत परिवहन एवं जल मार्ग, आयुष मंत्री, सर्वानंद सोनोवाल ने हरिद्वार के अलकनंदा घाट में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 'आयुष संवाद" उत्तराखंड आयुष: संसाधन एवं संभावनाएँ'कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम व बद्रीनाथ धाम का उल्लेख करते हुए कहा कि केदारनाथ में 400 करोड़ रुपए की योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास हुए हैं तथा अप्रैल में केदारनाथ में तीसरे चरण के कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के लिये 250 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पोत परिवहन और जल मार्ग, आयुष, भारत सरकार से उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान खोले जाने की मांग की।
- सर्वानंद सोनोवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई घोषणाएँ कीं-
  - राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत उत्तराखंड में 10 बेड का आयुष हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा।
  - राज्य के प्रत्येक ज़िले में एक-एक मोबाइल आयुष यूनिट (आयुष रथ) संचालित किये जाएंगे।
  - राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत राज्य में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तथा 50 बेड का यूनानी हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा।
  - राज्य में 100 आयुष वेलनेस सेंटर स्थापित करने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  - नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड की सहायता से राज्य के 200 स्कूलों में हर्बल गार्डन तथा तेरह ज़िलों में तेरह नर्सरियों की स्थापना की जाएगी।
  - मेडिकल प्लांट आदि की अवस्थापना के लिये प्रत्येक वन पंचायत को 15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
- इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में मर्म चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी तथा यह देश का प्रमुख केंद्र बनेगा। भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड को आयुष क्षेत्र के विकास के लिये सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने हवालबाग में दो दिवसीय आजीविका महोत्सव का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

- 17 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के हवालबाग में दोदिवसीय आजीविका महोत्सव का शुभारंभ किया। साथ ही हवालबाग में स्थित रूरल बिज़नेस इन्क्यूबेटर सेंटर का भी उद्घाटन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रूरल बिज़नेस इन्क्यूबेटर सेंटर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना एवं उद्यम स्थापना हेतु प्रारंभ से अंत तक उद्यमियों को सहयोग प्रदान करना है। इसके साथ-साथ युवाओं को रोज़गार सृजन, व्यवसाय सहयोग, नए विचार व तकनीक को बढ़ावा देना आदि इसके उद्देश्य हैं।
- इसके उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अल्मोड़ा व पौड़ी में रूरल बिज़नेस इन्क्यूबेटर सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर से आम आदमी को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी व जनप्रतिनिधि उत्तराखंड की प्रगति के लिये मिलकर कार्य करें। सभी विभागीय अधिकारियों को 10 वर्ष तक का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिये गए हैं, जिससे आने वाले उत्तराखंड के विकास की नींव रखी जा सके।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 49.19 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया तथा 27 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न योजनाओं के तहत चेक भी वितरित किये।
- आजीविका महोत्सव के दौरान उद्यान विभाग द्वारा यूरोपियन वेजिटेबल की खेती, पर्यटन विभाग द्वारा होमस्टे योजना, पशुपालन विभाग द्वारा व्यावसायिक मुर्गी पालन, उद्योग विभाग द्वारा मार्केटिंग एवं पैकेजिंग, एनआरएलएम व आजीविका द्वारा वैल्यू चैन व कृषि विभाग द्वारा वृक्ष आयुर्वेद कृषि पर कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।
- ज़िलाधिकारी वंदना सिंह ने आजीविका महोत्सव का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि कि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आजीविका के क्षेत्र में युवाओं, ग्रामीण महिलाओं, बेराज़गारों, कृषकों को बेहतर अवसर प्रदान करने के साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं व उद्योग स्थापित करने के संबंध में ऋण प्राप्त करने की जानकारी देना है।
- इस कार्यक्रम में भूटेखान पार्टी बाडमेर राजस्थान द्वारा राजस्थानी लोक नृत्य पेश किये। इस कार्यक्रम में उद्यान, कृषि, आजीविका, ग्राम्या विभाग, महेन्द्रा क्लब, मोक्सा रिटैट, सहकारिता, चाय विकास बोर्ड, राजकीय किशोरी गृह बख, आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन के स्टॉल भी लगाये गये।

'कोरोना से बचाव: एक सजग पहल' पुस्तक का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 20 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में डॉ. संतोष कुमार द्वारा लिखित पुस्तक 'कोरोना से बचाव: एक सजग पहल'का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस पुस्तक में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा किये गए कार्यों एवं अनुभवों के साथ कोविड महामारी से बचाव तथा अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारियों का समावेश किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तिका समाज से जुड़े प्रत्येक वर्ग के लिये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा जन-सेवा का सराहनीय कार्य किया गया।

'कांडा महोत्सव'

चर्चा में क्यों ?

- 23 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर जनपद के कांडा में आयोजित 'कांडा महोत्सव' का दीप प्रज्ज्वलित एवं पूजा-अर्चना कर शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- कांडा महोत्सव में मुख्यमंत्री द्वारा मेला समिति को 2 लाख तथा कांडा में सामुदायिक भवन के लिये 25 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। इसके अलावा ससोला में स्वीकृति एएनएम सेंटर के लिये धनराशि स्वीकृति करने तथा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिये अल्ट्रासाउंड एवं डायलिसिस की व्यवस्था करने की भी घोषणा की गई।

नोट :

- तत्पश्चात् मुख्यमंत्री ने बागेश्वर के विधानसभा कपकोट के केदारेश्वर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा कपकोट एवं बागेश्वर क्षेत्र की 27,331.13 लाख रुपए की लागत की 89 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
- विधानसभा कपकोट की 6843.03 लाख रुपए की लागत की 33 योजनाओं का लोकार्पण तथा 15632.94 लाख रुपए की 36 योजनाओं का शिलान्यास किया गया तथा विधानसभा बागेश्वर की 531.40 लाख रुपए की 4 योजनाओं का लोकार्पण तथा 4323.76 लाख रुपए की 16 योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
- मुख्यमंत्री द्वारा इसके पश्चात् सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में 500 एमपीएल क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण तथा 20 बैड के चिकित्सालय भवन व मीटिंग हॉल का शिलान्यास किया गया।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड जैसे युवा राज्य को आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार, उद्योग जैसे तमाम क्षेत्रों में हिंदुस्तान का नंबर वन राज्य बनाया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि जनपद में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं, जिसके लिये कार्य किया जा रहा है। कपकोट क्षेत्र में जड़ी-बूटी की अपार संभावनाएँ हैं, इसलिये इस क्षेत्र को जड़ी-बूटी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कपकोट में पॉलिटेक्निक के भवन निर्माण तथा सीएसडी कैंटीन के लिये आंकलन कर समाधान किया जाएगा।

सुशासन सूचकांक, 2021 में उत्तराखंड

चर्चा में क्यों ?

- 25 दिसंबर, 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें उत्तर-पूर्व एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को तृतीय रैंक प्राप्त हुई है।

प्रमुख बिंदु

- जीजीआई-2021 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों- समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में बाँटकर रैंकिंग दी गई है। जीजीआई-2021 तैयार करने के लिये 10 क्षेत्रों के 58 संकेतकों पर विचार किया गया है।
- उत्तराखंड ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.842 स्कोर के साथ उत्तर-पूर्व एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में तृतीय रैंक प्राप्त की है।
- उत्तराखंड के पिछले सूचकांक (2019) की तुलना में इस वर्ष के स्कोर में 0.5 प्रतिशत की कमी हुई है। पिछली बार इसका स्कोर 4.87 था, जो अब घटकर 4.84 हो गया है।
- उत्तराखंड ने मूलत: कृषि और संबद्ध क्षेत्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र तथा न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र में सुधार किया है।
- सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें उत्तराखंड की रैंकिंग तथा स्कोर निम्नलिखित हैं-

क्षेत्र	उत्तराखंड की रैंकिंग	स्कोर
1. कृषि और संबद्ध क्षेत्र	7वीं	0.386
2. वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र	तृतीय	0.650
3. मानव संसाधन विकास क्षेत्र	द्वितीय	0.607
4. सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र	7वीं	0.451
5. सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र	8वीं	0.627
6. आर्थिक शासन क्षेत्र	तृतीय	0.447
7. समाज कल्याण एवं विकास	6वीं	0.484
8. न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा	द्वितीय	0.493
9. पर्यावरण क्षेत्र	8वीं	0.138
10. नागरिक केंद्रित शासन	प्रथम	0.560

नोट :

नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड

चर्चा में क्यों ?

- 27 दिसंबर, 2021 को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 2019-20 के लिये अपने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई। इसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में उत्तराखंड 15वें स्थान पर है, वहीं केरल शीर्ष पर है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट को तीन भागों में बाँटा गया था- बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। छोटे राज्यों में मिज़ोरम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा जबकि नागालैंड सबसे नीचे रहा।
- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, उसके बाद दादरा और नगर हवेली दूसरे नंबर पर तथा दिल्ली तीसरे नंबर पर है।
- बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में उत्तराखंड 44.21 स्कोर के साथ 19 राज्यों में 15वें स्थान पर है। वही केरल 82.20 स्कोर के साथ पहले, तमिलनाडु 72.42 स्कोर के साथ दुसरे एवं तेलंगाना 69.96 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
- नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक एक भारित समग्र स्कोर है, जिसमें स्वास्थ्य प्रदर्शन के प्रमुख पहलुओं को शामिल करते हुए 24 संकेतक हैं।

वृहद् कौशल एवं सेवायोजन रोज़गार मेले का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 28 दिसंबर, 2021 को हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत एवं संसदीय कार्य, शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने संयुक्त रूप से वृहद् कौशल एवं सेवायोजन रोज़गार मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने 42 युवाओं एव युवतियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

- इस मेले का आयोजन कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग द्वारा किया गया है।
- मेले मे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के जनपदों में रोज़गार मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इन मेलों से युवाओं को रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं। रोज़गार मेले के लिये प्रदेश के बेरोज़गार युवा घर बैठे पंजीकरण करा सकते हैं।
- मुख्यमंत्री धामी ने कहा सरकार का मुख्य उद्देश्य रोज़गार के साथ-साथ स्वरोज़गार को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश मे 3700 होम स्टे पंजीकृत हैं जिसके अंतर्गत 8000 युवा एवं युवतियों को स्वरोज़गार मिल रहा है।
- उन्होंने कहा जिन विभागों में पद रिक्त हैं जल्दी से जल्दी भरने का कार्य किया जा रहा है। सरकार रोज़गार के साथ-साथ स्वरोज़गार के लिये वीर चंद्र गढ़वाली योजना में धनराशि को 25 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रावधान किया है साथ ही होमस्टे में और सब्सिडी बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिये एक वर्ष की आयु सीमा बढ़ा दी है तथा प्रदेश मे परीक्षा के फार्म के आवेदन शुल्क भरने के लिये आवेदक को कोई शुल्क नहीं देना होगा इसके साथ ही आईएएस, पीसीएस, एमबीबीएस, लोक सेवा आयोग की तैयारियों हेतु जो बच्चे प्रीक्वालीफाई कर देते हैं उन्हें आगे की तैयारियों हेतु 50 हज़ार रुपए सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं।
- उन्होंने कहा सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के सभी युवाओं को रोज़गार व स्वरोज़गार से जोड़ा जाएगा। एचएन इंटर कालेज मे वृहद् कौशल एवं सेवायोजन मेले में प्रदेश की 35 कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- रोज़गार मेले में विभिन्न जनपदों से आए 1150 युवा एवं युवतियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इस अवसर पर तीन कंपनियों द्वारा 162 युवाओं का वर्चुअल ऑनलाइन इंटरव्यू कर 7 लोगों को नियुक्ति दी गई।

नोट :

ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल

चर्चा में क्यों ?

- 29 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में तराई पूर्वी वन प्रभाग में ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ किया। यह राज्य का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा की क्रोकोडाइल ट्रेल के बनने से जहाँ क्रोकोडायल्स का प्राकृतिक वास में संरक्षण एवं संवर्द्धन होगा, वहीं क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसकी स्थापना से रोज़गार एवं आर्थिकीय गतिविधियों में वृद्धि होगी।
- उन्होंने कहा कि इसके बनने से इकोलॉजी, इकोनामी दोनों को ही मदद मिलेगी। इनके बनने से स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा, होमस्टे के माध्यम से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
- ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल सुरई इकोटूरिज़्म ज़ोन की पश्चिमी सीमा पर ककरा नाला स्थित है। यह नाला क्रोकोडाइल (मार्श मगरमच्छ) का प्राकृतिक वास स्थल है। मीठे पानी के स्रोतों में पाई जाने वाली मगरमच्छ की यह प्रजाति भूटान और म्याँमार जैसे तमाम देशों में विलुप्त हो चुकी है। अंडा देने वाली यह प्रजाति बेहद खतरनाक मानी जाती है। मौजूदा समय में इस नाले में 100 से अधिक मार्श मगरमच्छ हैं।
- पर्यटक मगरमच्छों को आसानी से देख सकें इसके लिये 4 किमी. लंबे नाले को चैनलिंग फेंसिंग करके ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल के रूप में विकसित किया गया है। राज्य के इस पहले क्रोकोडाइल ट्रेल में तीन व्यू प्वाइंट और कई वॉच टॉवर बनाए गए हैं ताकि मगरमच्छों को सुरक्षित तरीके से नज़दीक से देखा जा सके।

सुरई इकोटूरिज़्म ज़ोन में जंगल सफारी का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 29 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सुरई इकोटूरिज़्म ज़ोन में जंगल सफारी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी भी की। सुरई इकोटूरिज़्म ज़ोन प्रदेश का पहला ऐसा इकोटूरिज़्म ज़ोन है, जहाँ पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा जैव विविधता और वन्य जीवों की मौजूदगी वाले तराई पूर्वी वन प्रभाग को योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर उसके सुरई वन क्षेत्र को इको टूरिज़्म ज़ोन के रूप में तब्दील किया जाएगा, ताकि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का उपयोग स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोज़गार मुहैया करवाने में किया जा सके।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि वन और वन्य जीवों को आर्थिकी से जोड़ते हुए स्थानीय लोगों को स्वरोज़गार के अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर, 2021 को 'सीएम यंग ईकोप्रिन्योर योजना' देहरादून में लॉन्च की गई थी।
- इस योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। शुरुआत के तौर पर खटीमा में सुरई इकोटूरिज़्म ज़ोन विकसित कर उसमें जंगल सफारी प्रारंभ की जा रही है। ग्राम समितियों के जरिये इस योजना का संचालन किया जाएगा।
- जंगल सफारी शुरू होने से जिप्सी मालिक, चालक और गाइड के रूप में स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिलेगा। इसके लिये वन विभाग ने 30 जिप्सी संचालकों के साथ करार किया है। गाइड की भूमिका का सही निर्वहन करने के लिये कई युवकों को वन विभाग इसका प्रशिक्षण दे चुका है।
- सुरई इकोटूरिज़्म ज़ोन में पर्यटकों की आमद से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा। पूरे प्रदेश में इस योजना को विस्तार दिया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि सीएम यंग इको प्रिन्योर स्कीम के अंतर्गत नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर, इकोटूरिज़्म, वन्यजीव टूरिज़्म आधारित कौशल को उद्यम में परिवर्तित किया जाएगा।

नोट :

- सुरई वन क्षेत्र के वन मार्गों को जैव विविधता ट्रेल के रूप में विकसित किया गया है। यह क्षेत्र 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके सीमा में पूर्व दिशा में शारदा सागर डैम, पश्चिम में खटीमा नगर, उत्तर में मेलाघाट रोड तथा दक्षिण में पीलीभीत टाइगर रिज़र्व क्षेत्र सटा हुआ है।
- प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत इस वन क्षेत्र में साल के वृक्षों, चारागाह और पानी की प्रचुर मात्रा है। इन तमाम वजहों से यहाँ बाघों की आवाजाही बनी रहती है। इसके अलावा स्तनधारी जानवरों की लगभग 125, पक्षियों की 150 से अधिक और सरीसृपों को तकरीबन 20 प्रजातियाँ भी इस वन क्षेत्र में पाई जाती हैं।
- यहाँ के वन मार्गों को विकसित कर लगभग 40 किलोमीटर का ट्रेल जंगल सफारी के लिये तैयार कर लिया गया है, जिसमें जिप्सी में बैठकर पर्यटक दुर्लभ वन्यजीवों (रॉयल बंगाल टाइगर, भालू, चीतल, सांभर, काकड़, पैंगोलिन, कोरल साँप, पांडा आदि) का दीदार करने के साथ ही सुरम्य जंगलों, घास के मैदानों, प्राचीन शारदा नहर और सुंदर तालाबों का लुत्फ उठा सकेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,547 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी (नैनीताल) में आयोजित कार्यक्रम में 17,547 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इनमें 3420 करोड़ रुपए की 06 योजनाओं का लोकार्पण और 14,127 करोड़ रुपए की 17 योजनाओं का शिलान्यास शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एम्स के सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ के मेडिकल कालेज से कुमाऊँ और तराई क्षेत्र के लोगों के लिये विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। विभिन्न सड़क प्रोजेक्ट कुमाऊँ को बेहतर कनेक्टीवीटी देंगे। टनकपुरबागेश्वर रेल लाईन पर भी जल्दी से काम शुरू होगा।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी को नए साल की एक और सौगात दी जाएगी। हल्द्वानी के ओवरऑल विकास के लिये 2 हज़ार करोड़ की योजनाएँ लायी जाएंगी जिससे यहां अभूतपूर्व विकास होगा।
- केंद्र सरकार ने नैनीताल के देवस्थल पर भारत की सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी स्थापित की है। इससे देश-विदेश के वैज्ञानिकों को नई सुविधा तो मिली ही है, इस क्षेत्र को नई पहचान मिली है।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किये गए साढ़े सत्रह हज़ार करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास में पाँच हज़ार सात सौ सैंतालीस करोड़ रुपए की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना भी शामिल है।
- इस परियोजना से 300 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा जिससे प्रदेश न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में एक 'पावर हाउस'बनेगा बल्कि राज्य में बड़े स्तर पर रोज़गारों का सृजन भी होगा। साथ ही साथ इस परियोजना से 6 राज्यों को पीने का पानी भी उपलब्ध होगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कुमाऊँ संभाग में लगभग 500 करोड़ से अधिक की लागत से एम्स का सेटेलाइट सेंटर के प्रारंभ होने के पश्चात् उत्तराखंड भारत का वह पहला राज्य बन जाएगा जहाँ एम्स के अतिरिक्त एम्स का सेटेलाइट सेंटर भी स्थापित होगा।
- पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों तक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाने के उद्देश्य से 455 करोड़ रुपए की लागत से पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। सरकार चारधाम कॉरिडोर की तर्ज पर कुमाऊँ क्षेत्र में मानस खंड कॉरिडोर बनाने के लिये भी प्रयासरत है। इससे जहाँ एक ओर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर पूरे कुमाऊँ के आधारभूत ढाँचे को भी बल मिलेगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत चवालिस वर्षों से लंबित जमरानी बांध एवं पेयजल योजना शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रही है। हल्द्वानी में एकीकृत शहरी मूलभूत ढाँचे के विकास (इन्टीग्रेटेड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन हल्द्वानी) के लिये केंद्र सरकार के गंभीर प्रयासों से लगभग इक्कीस सौ करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं।

नोट :